

साइबरपीस कोर • डिजिटल वेलबीइंग सीरीज़

सूचना सत्यनिष्ठा और संज्ञानात्मक सुरक्षा (Information Integrity & Cognitive Security)

दुष्प्रचार (Disinformation), भ्रामक सूचना (Misinformation) और द्वेषपूर्ण सूचना (Malinformation)

सूचना विकार (Information Disorder) को समझना — झूठी और हानिकारक सामग्री कैसे फैलती है, और
उसे कैसे पहचानें व उसका प्रतिरोध करें।

आप क्या सीखेंगे (WHAT YOU WILL LEARN)

सत्र की रूपरेखा

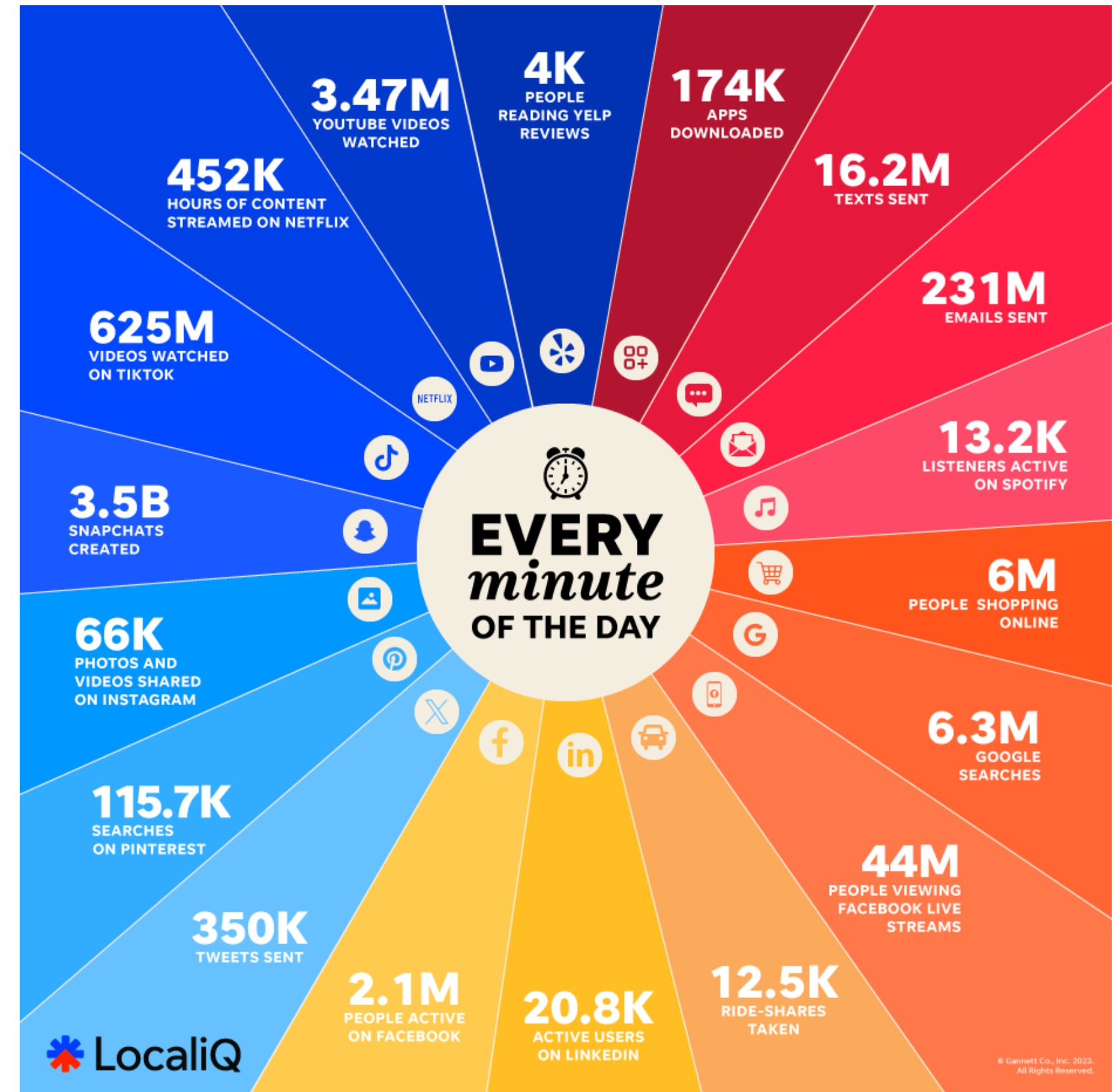
- 1 डिजिटल दुनिया और सूचना विकार (Information Disorder) को समझना
- 2 फ़ेक न्यूज़ (Fake News) और डीपफ़ेक (Deepfake)
- 3 सोशल मीडिया में हेर-फेर (Social Media Manipulation)
- 4 तथ्य-जांच (Fact-Checking)
- 5 भारतीय कानूनों में प्रावधान

आज की डिजिटल/साइबर दुनिया – 1

- साइबर स्पेस (Cyber Space) — खुला, सर्वव्यापी, आभासी, सीमाहीन और (अधिकतर) गुमनाम।
- 8.1 अरब लोगों में से 5.5 अरब से अधिक इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़े हुए।
- दुनिया भर में किसी से भी, तुरंत जुड़ना और संवाद करना संभव।
- इंटरनेट — खुद को अभिव्यक्त करने का एक मंच।
- सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया कंटेंट:
 - लगभग 5.5 अरब सोशल मीडिया उपयोगकर्ता!
 - लगभग 20 करोड़ सक्रिय वेबसाइटें
 - एंड्रॉयड पर 30 लाख से अधिक ऐप्स
 - भारत में लगभग 60 करोड़ लोग व्हाट्सऐप पर, 40 करोड़ फेसबुक पर...
- कोई भी उपलब्ध डोमेन नेम (Domain Name) कहीं से भी खरीदा जा सकता है।
- लगभग 20 करोड़ सक्रिय वेबसाइटें मौजूद हैं।
- वायरैलिटी (Virality)/प्रसार — और इसलिए ऑनलाइन नुकसान पहुंचाने की क्षमता — भौतिक दुनिया की तुलना में कहीं तेज और अधिक है।
- एआई (AI) ने लगभग हर क्षेत्र में सामग्री बनाने, पूर्वानुमान लगाने, विश्लेषण करने और स्वचालित कार्य करने की क्षमताएं देकर पूरा परिदृश्य ही बदल दिया है।
- बड़ी संख्या में ऐप्स सामग्री निर्माण और संपादन (Editing) की सुविधाएं दे रहे हैं।

आज की डिजिटल/साइबर दुनिया – 2

- दुनिया प्रतिदिन 402.74 मिलियन टेराबाइट (Terabytes) डेटा उत्पन्न करती है — यानी लगभग 147 ज़ेटाबाइट (Zettabytes) प्रति वर्ष।
- इंटरनेट पर सूचना का विशाल भंडार।
 - इसमें से कुछ सूचना भ्रामक, गलत, हानिकारक, फर्जी/झूठी, अश्लील, निजता (Privacy) भंग करने की क्षमता रखने वाली या किसी न किसी रूप में गैरकानूनी भी है।



भारत और डिजिटल दुनिया

- हमारे पास लगभग 100 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हैं।
- बढ़ती इंटरनेट पहुंच, डेटा स्पीड और डिजिटल में बिताया जाने वाला समय।
- सबसे अधिक उपयोग होने वाले डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure – DPI) में से एक।
- बहु-सांस्कृतिक, बहु-धार्मिक, बहु-भाषी — हर ओर विशाल विविधता।
- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार।

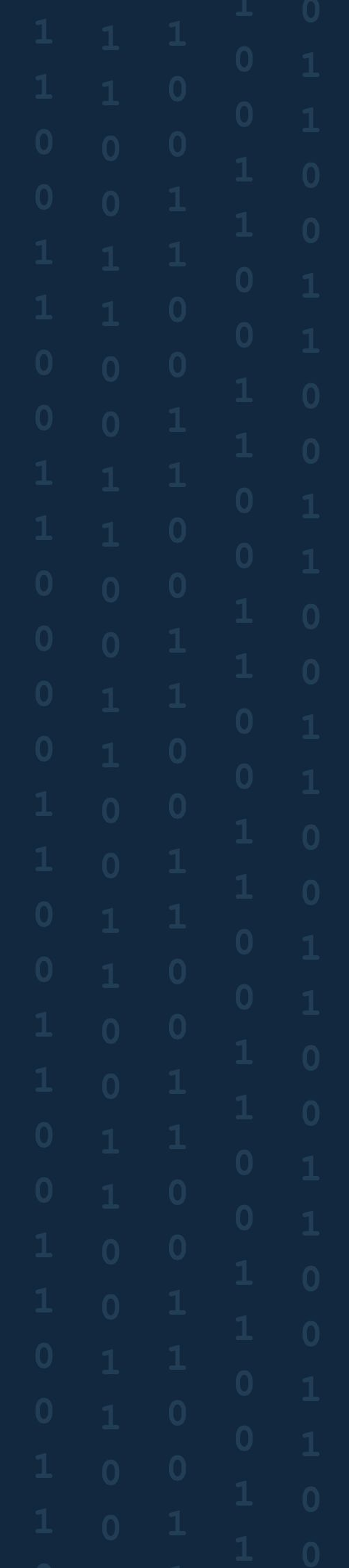
धारणा (Perception) Vs. वास्तविकता (Reality)

(कहानी: अंधों और हाथी की एक झलक: हाथी और अलग-अलग अनुभव)



सूचना विकार (Information Disorder) को समझना

झूठी और हानिकारक सामग्री के पीछे की शब्दावली और ढांचा



सूचना विकार की परिभाषा

- ♦ "सूचना विकार" (Information Disorder) वह शब्द है जिससे शोधकर्ता ऑनलाइन झूठी और हानिकारक सूचना की समस्याओं के पूरे परिदृश्य का वर्णन करते हैं — इसे सबसे पहले व्यापक रूप से शोधकर्ता क्लेयर वार्डल और हुसैन देराख़शान ने प्रस्तुत किया।
- ♦ यह "फ़ेक न्यूज़" (Fake News) के एकल लेबल से आगे बढ़कर समस्याग्रस्त सामग्री के प्रकारों में दो प्रश्नों के आधार पर अंतर करता है: क्या यह झूठी है, और क्या इसका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना है?
- ♦ इन भेदों को समझने से आप उचित प्रतिक्रिया दे पाते हैं — एक वास्तविक गलती के लिए सुधार चाहिए; एक संगठित छल के लिए अलग तरह की प्रतिक्रिया चाहिए।
- ♦ तीन मुख्य श्रेणियां हैं — भ्रामक सूचना (Misinformation), दुष्प्रचार (Disinformation) और द्वेषपूर्ण सूचना (Malinformation)।

हर "झूठी" सामग्री एक ही तरह से नहीं बनती, और हर "सच्ची" सामग्री अच्छे इरादे से साझा नहीं की जाती।

इरादा (Intent) और सटीकता (Accuracy) — ये दो अलग-अलग प्रश्न हैं।

सूचना (Information), गलत सूचना (Mis-information) और भ्रामक या षड्यंत्रकारी सूचना (Dis-information)

सूचना (Information - सही और सत्यापित जानकारी)

- उदाहरण: "भारत के चंद्रयान-3 मिशन ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की।"
- विशेषता:
 - यह पूरी तरह सच है।
 - इसके पीछे आधिकारिक आंकड़े और सबूत होते हैं।
 - इसका उद्देश्य लोगों को सही ज्ञान देना है।

गलत सूचना (Mis-information - अनजाने में फैलाई गई झूठी बात)

- उदाहरण: किसी पुराने तूफान की तस्वीर को यह कहकर सोशल मीडिया पर शेयर करना कि यह "कल रात दिल्ली में आए तूफान की तस्वीर है," जबकि भेजने वाले को सच नहीं पता था।
- विशेषता:
 - यह जानकारी झूठी होती है।
 - भेजने वाले को लगता है कि वह सच बोल रहा है।
 - लोग बिना सोचे-समझे इसे आगे बढ़ा (forward) देते हैं।

भ्रामक सूचना (Dis-information - जानबूझकर फैलाया गया झूठ)

- उदाहरण: चुनाव जीतने के लिए किसी नेता के पुराने और अलग संदर्भ वाले वीडियो को एडिट करके यह दिखाना कि वह देश के खिलाफ बोल रहे हैं।
- विशेषता:
 - यह पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठी होती है।
 - इसे जानबूझकर समाज में नफरत या भ्रम फैलाने के लिए बनाया जाता है।
 - इसके पीछे कोई न कोई निजी या राजनीतिक स्वार्थ होता है।

डीपफेक (Deepfake) क्या हैं?

- ◆ डीपफेक एक सिंथेटिक मीडिया (Synthetic Media) है — वीडियो, ऑडियो या चित्र — जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) की मदद से इस तरह बनाया या बदला जाता है कि कोई व्यक्ति वह करता या कहता हुआ दिखे जो उसने कभी किया ही नहीं।
- ◆ यह नाम "डीप लर्निंग" (Deep Learning — एआई तकनीक) और "फ़ेक" (Fake) को मिलाकर बना है।
- ◆ डीपफेक हानिरहित मनोरंजन (फेस-स्वैप फिल्टर) से लेकर गंभीर खतरों तक फैले हैं: गढ़े हुए राजनीतिक भाषण, अधिकारियों का रूप धरकर की गई धोखाधड़ी वाली वॉइस कॉल, और बिना सहमति की अश्लील सामग्री।
- ◆ यह तकनीक नाटकीय रूप से सस्ती और आसान हो गई है — कुछ ही वर्षों में शोध प्रयोगशालाओं से निकलकर मुफ्त उपभोक्ता ऐप्स तक पहुंच गई है।

हाल के वर्षों में, एक विश्वसनीय डीपफेक आवाज़ (Voice Clip) तैयार करने के लिए केवल कुछ सेकंड का नमूना ऑडियो ही पर्याप्त हो सकता है।

एआई द्वारा बदली गई तस्वीर/ कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा रूपांतरित चित्र



गहन नकल (डीपफ़ेक) तकनीक जहाँ स्पष्ट रूप से मूल्य जोड़ती है:

शिक्षा और कॉर्पोरेट प्रशिक्षण

- एआई ट्यूटर और आभासी शिक्षक जो कई भाषाओं और बोलियों में पढ़ाते हैं।
- इमर्सिव ऐतिहासिक पाठ जहाँ ऐतिहासिक हस्तियाँ “अपनी आवाज़” में बोलती हैं, जिससे सामग्री अधिक आकर्षक बनती है
- यथार्थवादी प्रशिक्षण सिमुलेशन (जैसे ग्राहक सेवा, सुरक्षा ड्रिल) जिनमें सिंथेटिक कर्मचारी होते हैं, जिससे उत्पादन लागत कम होती है और स्केलेबिलिटी बढ़ती है।

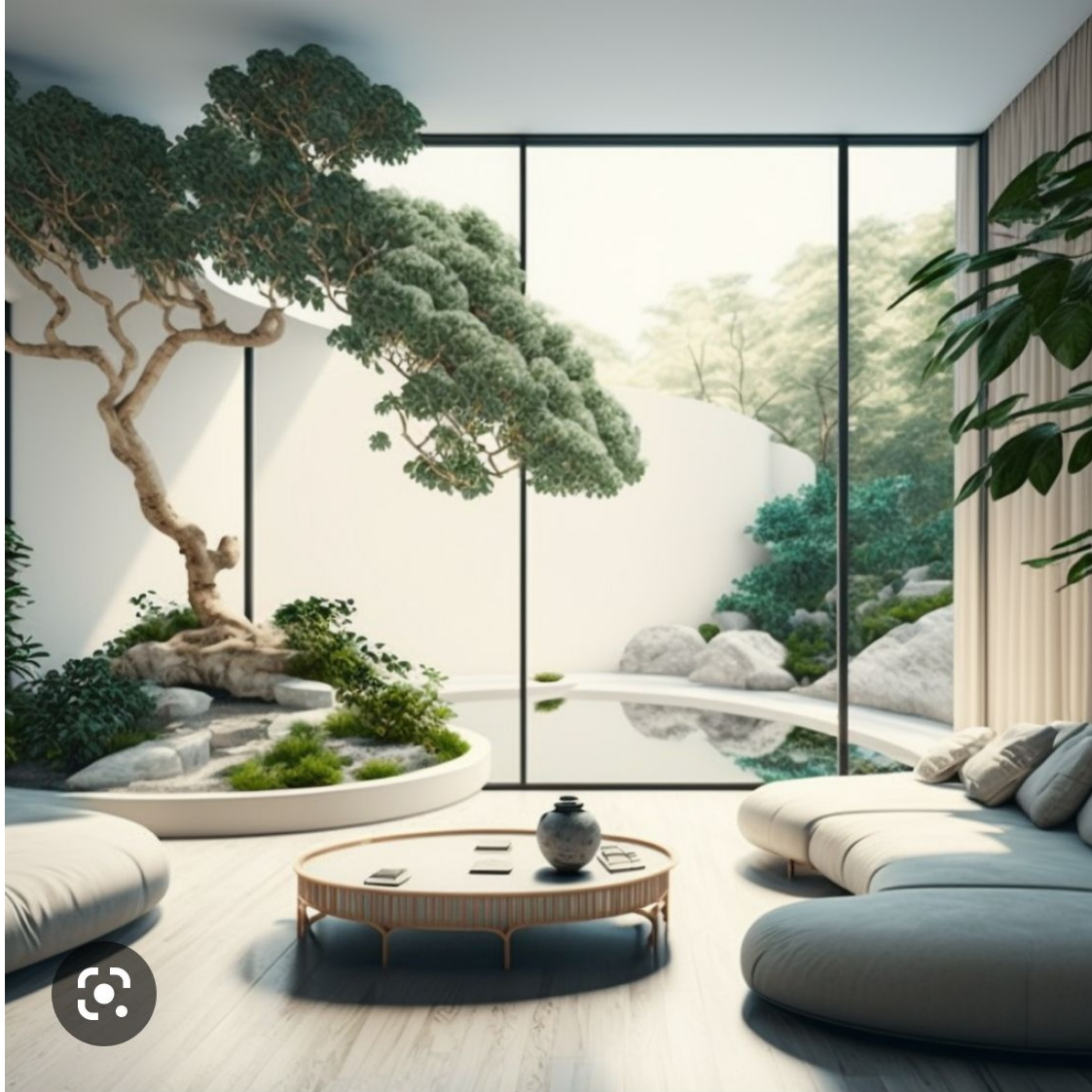
सुलभता और समावेशन

- बोलने या गतिशीलता संबंधी बाधाओं वाले लोगों के लिए व्यक्तिगत अवतार और वॉइस सिंथेसिस, जिससे वे वीडियो कॉल और ऑनलाइन सीखने में बेहतर भाग ले सकते हैं।
- लिप-सिंक संरेखण के साथ बहुभाषी डबिंग, ताकि वैश्विक दर्शक प्रस्तुतकर्ताओं को अपनी भाषा में स्वाभाविक रूप से बोलते हुए देख सकें।

•फ़िल्म, मीडिया और रचनात्मक उत्पादन

- VFX लागत कम करते हुए कहानी सुनाने के लिए कलाकारों की उम्र कम दिखाना या किरदारों को पुनर्जीवित करना।
- प्रवेश में बाधाएँ कम करना: छोटी टीमों बड़े क्रू या महंगे शूट के बिना उच्च-गुणवत्ता वाली सामग्री बना सकती हैं।
- क्षेत्रीय संस्कृतियों, बोलियों और पसंद के अनुरूप किरदारों का स्थानीयकरण और अति-स्थानीयकरण।

एआई द्वारा बनाई गई तस्वीरें



सूचना विकार और उसका प्रभाव

आसपास के समाचार और कहानियां

- ऑपरेशन सिंदूर
- अमेरिका/इजराइल और ईरान युद्ध
- हाल के छात्र/सीजेपी विरोध प्रदर्शन
- "डिजिटल अरेस्ट" (Digital Arrest) सहित डिजिटल घोटाले
- पेपर लीक की अफवाहें
- चुनाव के समय भ्रामक सूचना और डीपफेक

किन पर प्रभाव

- व्यक्ति — जिनमें छात्र भी शामिल हैं
- समाज या समाज का कोई विशेष वर्ग (लोक व्यवस्था)
- भारत की संप्रभुता और अखंडता / राज्य की सुरक्षा

डीपफेक की पहचान: चेतावनी संकेत (Red Flags)

01

पलक झपकने का अस्वाभाविक पैटर्न, या पलक का बिल्कुल न झपकना

02

चेहरे या हेयरलाइन के किनारों पर धुंधलापन या विकृति

03

ऑडियो का होंठों की गति से पूरी तरह मेल न खाना

04

त्वचा की अस्वाभाविक बनावट, रोशनी या छाया

05

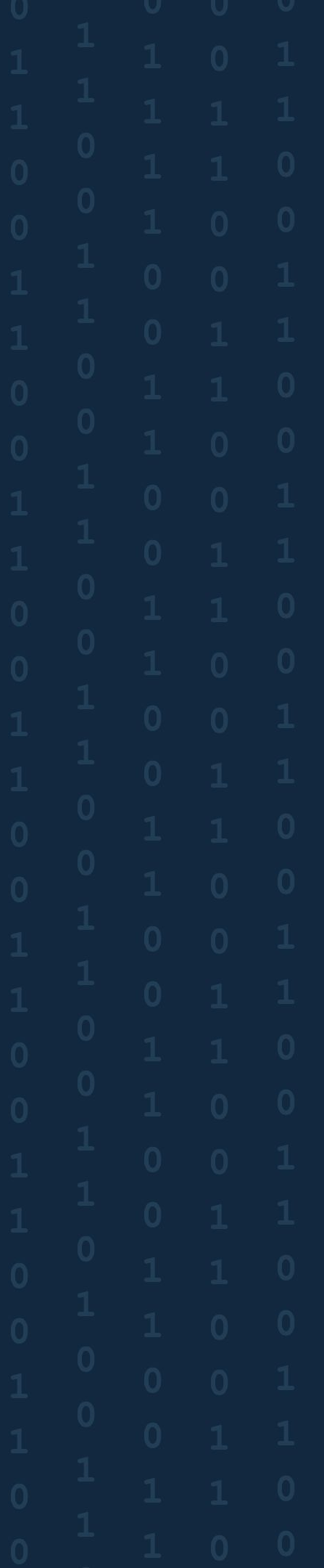
क्लोन की गई आवाज़ (Cloned Voice) में सपाट या रोबोट जैसा स्वर

06

किसी सनसनीखेज दावे की पुष्टि करने वाला कोई स्रोत नहीं

तथ्य-जांच (Fact-Checking) तकनीकें और सत्यापन उपकरण

किसी दावे पर भरोसा करने या उसे साझा करने से पहले जांचने के व्यावहारिक तरीके



प्रमुख सरकारी और स्वतंत्र फैक्ट चेकिंग यूनिट

- भारत में फर्जी खबरों (Fake News) और सोशल मीडिया पर फैलने वाले भ्रम को रोकने के लिए कई सरकारी और स्वतंत्र एजेंसियां/वेबसाइट्स
- सरकारी फैक्ट चेकिंग यूनिट
 - **PIB Fact Check:** यह भारत सरकार के **प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau)** की आधिकारिक शाखा है। इसका मुख्य काम केंद्र सरकार, मंत्रालयों और उसकी योजनाओं से जुड़ी झूठी खबरों का पर्दाफाश करना है।

प्रमुख स्वतंत्र फैक्ट चेकिंग एजेंसियां

BOOM Live: भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट्स में से एक है, जो अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला सहित कई भाषाओं में काम करती है।

Alt News: गैर-लाभकारी संस्था (Non-profit organization) जो मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले राजनीतिक और सांप्रदायिक दावों की सत्यता जांचती है।

Factly: यह एजेंसी डेटा और सरकारी रिकॉर्ड्स के आधार पर खबरों और दावों को प्रमाणित करती है।

FactCrescendo: देश की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं (जैसे मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु आदि) में प्रमुखता से फैक्ट-चेक करने वाली बड़ी स्वतंत्र एजेंसी है।

Logically: यह संस्था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक टूल्स का उपयोग करके बड़े पैमाने पर भ्रामक जानकारियों की पहचान करती है।

मुख्यधारा मीडिया की फैक्ट-चेक विंग्स

इंडिया टुडे ग्रुप की India Today Fact Check

दैनिक जागरण (Jagran New Media) की फैक्ट-चेकिंग विंग : Vishvas News

The Quint (WebQoof)

सूचना विकार से निपटना

तथ्य-जांचकर्ताओं (Fact-Checkers) की भागीदारी

- ऑनलाइन समाचार प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग
- सरकारों की अपनी तथ्य-जांच एजेंसियां

स्वतंत्र तथ्य-जांचकर्ता (Independent Fact-Checkers)

ऐसे संगठन जो दावों की पुष्टि करते हैं और पारदर्शी, स्रोत-सहित कार्यप्रणाली प्रकाशित करते हैं — अक्सर इंटरनेशनल फैक्ट-चेकिंग नेटवर्क (International Fact-Checking Network) के हस्ताक्षरकर्ता।

सरकार की विधायी पहलें

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act)
- IT नियम, 2021 — जैसा कि 2026 में संशोधित

मीडिया साक्षरता संगठन (Media Literacy Organizations)

साइबरपीस कोर (CyberPeace Corps) जैसे समूह जनता के लिए प्रशिक्षण, गाइड और रिपोर्टिंग टूल उपलब्ध कराते हैं।



PIB Fact Check ✓
@PIBFactCheck

⚠️ #QuantumAI SCAM ALERT! ⚠️

A digitally manipulated video of Shaktikanta Das, Principal Secretary-2 to Prime Minister is circulating online wherein he is endorsing 'Quantam AI' investment platform

#PIBFactCheck:

✗ The video has been digitally altered using artificial intelligence

✓ No such scheme exists or is being endorsed by the Shaktikanta Das or the Government of India.

▶ Do not fall for manipulated content circulating online that aims to deceive the citizens.

● Report suspicious content related to the Government of India to
@PIBFactCheck

☎ 8799711259

✉ factcheck@pib.gov.in

@PMOIndia @FinMinIndia @MIB_India
@airnewsalerts @DDNewslive



Digitally altered video featuring Principal Secretary-2 to Prime Minister circulating online

**PM NARENDRA MODI
CLOSES THE REGISTRATION
5 AUGUST, 2026
8 PM - LAST DAY TO REGISTER**



INVESTMENT DAILY INCOME MONTHLY INCOME
₹22,000 ₹63,351 ₹16,67,567

00:25

@PIBFactCheck

Instagram /PIBFactCheck

Facebook /PIBFactCheck

Telegram t.me/PIB_FactCheck

#PIBFactCheck

<https://x.com/PIBFactCheck/status/2084969179216822334>



India Post is **not** offering any free Dak Sewa Gifts



@PIBFactCheck @ /PIBFactCheck f /PIBFactCheck t.me/PIB_FactCheck

STRATURKA

Straturka ✓

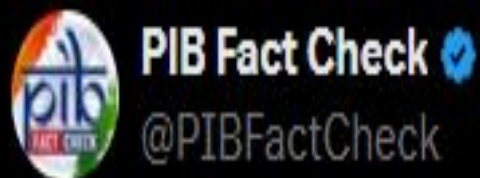
@straturka

Follow

India has requested Israel to sign a defense pact to counter upcoming Pak-Saudi-Turk treaty.

- Pakistani sources





🚩 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डिजिटली ऑल्टर्ड वीडियो साझा कर यह दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा सभी छात्रों को 3 महीने के लिए मुफ्त मोबाइल रिचार्ज दिया जाएगा।

#PIBFactCheck

✗ यह दावा फर्जी है।

✓ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।

♦ केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल myscheme.gov.in पर ही भरोसा करें।

♦ केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी संदिग्ध तस्वीर, वीडियो अथवा संदेश को @PIBFactCheck पर भेजें, वास्तविक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे।

व्हाट्सएप: +91 8799711259

ईमेल: factcheck@pib.gov.in



00:10

वैश्विक तथ्य-जाँच (Fact-Checking) वेबसाइटें

- **Snopes:** वायरल इंटरनेट मीम्स, शहरी किंवदंतियों (Urban Legends) और ऑनलाइन अफवाहों/झूठे दावों की जाँच करता है।
- **PolitiFact:** राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक व्यक्तियों के बयानों की सत्यता को “**Truth-O-Meter**” के माध्यम से जाँचता और रेटिंग देता है।
- **FactCheck.org:** मुख्य रूप से सार्वजनिक नीतियों, राजनीतिक बहसों और सार्वजनिक बयानों की तथ्य-जाँच पर केंद्रित है।
- **AFP Fact Check:** अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर वायरल होने वाली तस्वीरों, वीडियो और दावों की तथ्य-जाँच कर गलत जानकारी का खंडन करता है।

भारतीय तथ्य-जाँच (Fact-Checking) वेबसाइटें

- **PIB Fact Check:** भारत सरकार की नीतियों, योजनाओं और सरकारी दावों से संबंधित जानकारी को सत्यापित करने के लिए आधिकारिक पोर्टल।
- **FactChecker.in:** भारत में सार्वजनिक बयानों, दावों और आँकड़ों की स्वतंत्र रूप से जाँच करने वाली मीडिया पहल।

तथ्य-जाँच एग्रीगेटर (Aggregators)

- **Google Fact Check Tools:** विभिन्न स्रोतों द्वारा की गई तथ्य-जाँच को खोजने और सत्यापित दावों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सहायता करने वाला उपकरण।

मार्केटिंग और ई-कॉमर्स

- कपड़े, चश्मे और कॉस्मेटिक्स के लिए आभासी ट्राई-ऑन
- पैमाने पर व्यक्तिगत वीडियो संदेश (जैसे अनुकूलित ऑनबोर्डिंग या उत्पाद स्पष्टीकरण), जब स्पष्ट रूप से सिंथेटिक होने का उल्लेख किया गया हो

साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकथाम

- सुरक्षा और कानून प्रवर्तन टीमों को गहन नकल घोटालों और वॉइस-क्लोनिंग हमलों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करने में सिंथेटिक मीडिया का उपयोग।
- पहचान प्रणालियों का तनाव परीक्षण और बेहतर प्रमाणीकरण वर्कफ़्लो बनाना।

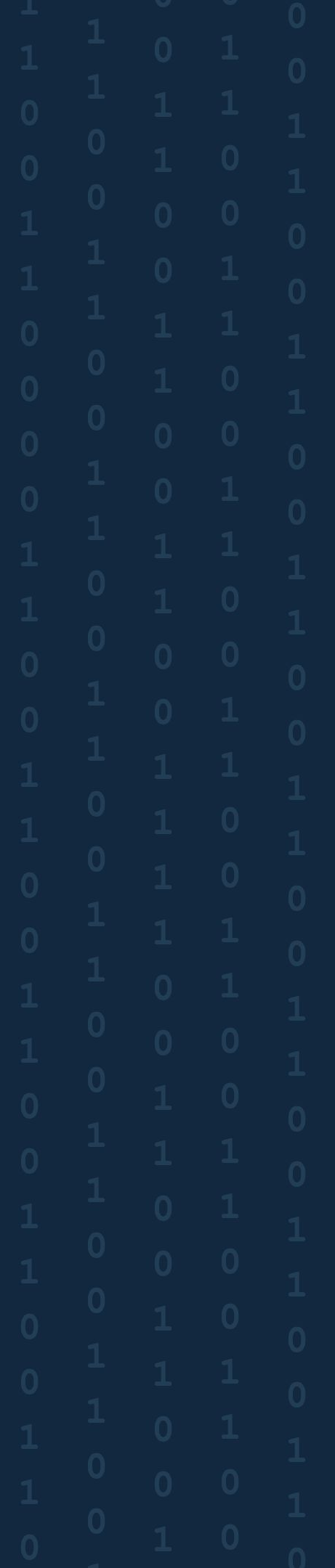
समाचार और सार्वजनिक संचार

- आभासी रिपोर्टर और सारांशित प्रसारण जिन्हें विभिन्न दर्शकों के लिए तेज़ी से स्थानीय बनाया जा सकता है।
- आपातकालीन स्थितियों में त्वरित स्पष्टीकरण बनाना, जब मानवीय प्रस्तुतकर्ता तुरंत उपलब्ध न हों (स्पष्ट लेबलिंग के साथ)।

भारतीय कानूनों में प्रावधान

IT (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021

The IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 — (IT Rules, 2021)



IT नियम, 2021 की यात्रा और इसके संशोधन

विकास की समयरेखा: 2011 नियम → 2021 व्यापक बदलाव → 2022-23 सख्ती → 2026 एआई/SGI विनियमन (2026 संशोधन 20 फरवरी 2026 से प्रभावी)

- **दायरा** — व्यावहारिक रूप से सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म: मध्यवर्ती (Intermediaries) और प्रकाशक (Publishers)
- **उचित सावधानी (Due Diligence) की संरचना** — नीतियां | नोटिस | टेकडाउन (Takedown) | सहयोग | डेटा प्रतिधारण (Retention)
- **शिकायत निवारण (Grievance Redressal)** — शिकायत अधिकारी, पावती, निपटान की समय-सीमाएं
- **शिकायत अपीलीय समिति (Grievance Appellate Committee – GAC)** — मॉडरेशन विवादों के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय निकाय (3 समितियां)
- **2021 नियमों का दर्शन** — जवाबदेही | ट्रेसेबिलिटी (Traceability) | पारदर्शिता | उपयोगकर्ता सुरक्षा | संप्रभु निगरानी
- **प्रतिबंधित सामग्री का ढांचा** — गैरकानूनी, मानहानिकारक, अश्लील, निजता भंग करने वाली, भ्रामक, नाबालिगों के लिए हानिकारक
- **ट्रेसेबिलिटी की आवश्यकता** — गंभीर अपराधों के लिए पहले प्रवर्तक (First Originator) की पहचान

2026 संशोधनों के प्रमुख क्षेत्र

नई परिभाषा

'सिंथेटिक रूप से जनित सूचना' (Synthetically Generated Information) — नियम 2(wa) के अंतर्गत औपचारिक रूप से परिभाषित

तेज़ समय-सीमाएं

सरकारी आदेश: 36 घंटे → 3 घंटे · शिकायतें: 15 दिन → 7 दिन · व्यक्तिगत नुकसान पर कार्रवाई: 24 घंटे → 2 घंटे

उचित सावधानी — नियम 3(3)

एआई सामग्री की अनिवार्य लेबलिंग (Labeling), मेटाडेटा एम्बेडिंग, प्रोवेनेंस (Provenance) ट्रैकिंग

SSMI द्वारा अतिरिक्त सावधानी — नियम 4(1A)

SSMI को उपयोगकर्ता घोषणाएं लेनी होंगी, सटीकता सत्यापित करनी होगी और SGI पर एआई लेबल दिखाने होंगे

BNS ने IPC की जगह ली

नियम 7 अद्यतन — भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की जगह ली

पहचान का खुलासा

प्लेटफॉर्म उल्लंघन करने वाले उपयोगकर्ता की पहचान पीड़ितों और अधिकारियों को बता सकते हैं

प्रमुख कारण:

- एआई-जनित भ्रामक सूचना से निपटना
- प्रतिरूपण (Impersonation) और डीपफेक दुरुपयोग की रोकथाम
- बिना सहमति की अंतरंग छवियों (NCII) से पीड़ितों की रक्षा
- जन विश्वास और डिजिटल सत्यनिष्ठा की रक्षा
- वायरैलिटी से संभावित नुकसान को देखते हुए प्रवर्तन समय-सीमाओं में तेज़ी

मुख्य निष्कर्ष

1. गलत सूचना अक्सर अनजाने में फैलती है, जबकि भ्रामक सूचना जानबूझकर फैलाई जाती है.
2. सही जानकारी वही है जो सत्यापित, प्रमाणित और आधिकारिक स्रोतों पर आधारित हो.
3. तस्वीर, वीडियो और ऑडियो हमेशा सच नहीं होते; उन्हें एडिट या बदलकर भ्रम फैलाया जा सकता है.
4. कोई भी संदेश बार-बार फॉरवर्ड हुआ हो, इसका मतलब यह नहीं कि वह सच है.
5. फर्जी व्हाट्सएप संदेशों और फर्जी लिंक की पहचान करना सीखना चाहिए.
6. किसी संदेश को आगे भेजने से पहले उसके स्रोत, URL और तथ्य की जांच करनी चाहिए.
7. भावनात्मक रूप से उकसाने वाले, राजनीतिक या धार्मिक रूप से पक्षपाती संदेशों से सावधान रहना चाहिए.
8. डीपफेक तकनीक का उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरह से हो सकता है, इसलिए पारदर्शिता और लेबलिंग जरूरी है.
9. फर्जी जानकारी की रिपोर्ट करना, ब्लॉक करना और तथ्य-जांच वेबसाइटों का उपयोग करना डिजिटल सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

निष्कर्ष और आगे की राह

- इंटरनेट सूचना का समृद्ध स्रोत है, लेकिन हर सूचना का सही और प्रामाणिक होना जरूरी नहीं।
- इंटरनेट पर बहुत सारी भ्रामक सूचना (Misinformation), दुष्प्रचार (Disinformation) और द्वेषपूर्ण सूचना (Malinformation) मौजूद है।
- हमेशा प्रामाणिक साइटों पर ही जाएं (जैसे सरकारी वेबसाइटों के लिए .gov.in या .nic.in)।
- हमेशा आधिकारिक प्ले स्टोर (Play Store) से डाउनलोड किए गए ऐप्स ही इस्तेमाल करें।
- समाचार सहित किसी भी सूचना की प्रामाणिकता प्रामाणिक स्रोतों या तथ्य-जांच साइटों से सत्यापित करें।
- जब तक सूचना की प्रामाणिकता पर पूरा भरोसा न हो, उसे आगे फॉरवर्ड (Forward) न करें।
- देखना ही मान लेना नहीं है! इसलिए सजग रहें।